समक्ष गुरविंदर सिंह गिल, न्यायमूर्ति ।

लछमन दास- याचिकाकर्ता

बनाम

अमरजीत सिंह साहनी और अन्य- प्रतिवादी

2019 का सीआर नंबर 6310

अक्टूबर 06, 2020

हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1973, धारा 13-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश XIII नियम 3 और आदेश III नियम 1-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 3- मकान मालिक/प्रतिवादी ने आवासीय परिसर से किरायेदार/याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए 1973 अधिनियम की धारा 13 के तहत आवेदन दायर किया- किराए और व्यक्तिगत आवश्यकता का भुगतान न करने के आधार- किराया नियंत्रक ने अनंतिम किराए का आकलन किया और किरायेदार को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया- अपील दायर की गई- पक्षकारों ने मामले का निपटारा कर दिया अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 25.03.2019 को उनके बयान दर्ज करवाकर - मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 20.04.2019 तक स्थगित कर दिया गया - किरायेदार ने दिए गए बयान का सम्मान करने के बजाय, योग्यता के आधार पर अपील के निपटान की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसे मकान मालिक और उसके वकील द्वारा इस स्वयं के (किरायेदार के) वकील के साथ मिलीभगत से बयान देने के लिए लुभाया गया था - अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज किया गया आवेदन - उस प्रावधान का दावा करते हुए पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई मुद्दा यह था कि क्या किसी मामले में समझौता किया गया है, यह अनिवार्य था कि इस तरह के समझौते को एक उपकरण के माध्यम से लिखित रूप में लिया जाए - कानून की स्थिति, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पता चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी पक्ष या उसके वकील द्वारा समझौते के प्रति दिया गया बयान जिसे लेखन, एक लिखित समझौते के रूप में अच्छा है और आदेश XXIII नियम 3 सीपीसी की आवश्यकताओं को उचित ठहराएगा - कानून की अदालत में एक न्यायिक अधिकारी के समक्ष दर्ज किए गए बयानों को कुछ शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न्यायालय के बाहर तैयार किए गए समझौते के साधन से कम पवित्रता नहीं कहा जा सकता है - आगे आयोजित किया गया, एकमात्र अपवाद जिसके तहत एक

पक्ष उसके या उसके वकील द्वारा दिए गए बयान से बाहर निकल सकता है, वह हो सकता है जहां वह यह स्थापित करने में सक्षम है कि इसे धोखाधड़ी या धोखे के माध्यम से बनाया गया था - ऐसे मामले में भी उसे आदर्श रूप से इस तरह के निर्णय / डिक्री को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता होगी - तथ्यों पर, किरायेदार द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार मिलीभगत या प्रलोभन स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं - बार काउंसिल में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई - याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना जाता है कि कानून की स्थिति, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों से पता चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी पक्ष द्वारा या उसके वकील द्वारा समझौते के प्रति दिया गया बयान जो लिखित रूप में लिया जाता है, एक लिखित समझौता के रूप में अच्छा है और आदेश 23 नियम 3 सीपीसी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, विशेष रूप से नियम 3 में प्रावधान के संबंध में, जिसे वर्ष 1976 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, अर्थात् 2007-08 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। *"पार्टियों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित"*। हमारे उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के निर्णय का भी उल्लेख करना असंगत नहीं होगा जिसमें दस्तावेज शब्द की परिभाषा के संदर्भ में इसी मुद्दे पर चर्चा की गई है। *श्रीमती रक्षा रानी बनाम राम लाल (डीबी)* 1987 एआईआर (पंजाब एंड एचआर) 60 से प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार है:

> "5 .... बेशक, ट्रायल कोर्ट द्वारा पार्टियों के बयान दर्ज किए गए थे जिनमें समझौते की शर्तें थीं जिन पर उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। क्या यह कहा जा सकता है कि समझौते को लिखित रूप में नहीं माना जाना चाहिए और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाना चाहिए? क्या कागज के एक टुकड़े पर लिखे गए और उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों को न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में दिए गए उनके स्पष्ट बयानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिस पर उन्होंने विधिवत हस्ताक्षर किए थे? हमारी स्पष्ट राय में, नियम 3 के पहले भाग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संतुष्ट किया जाता है जब पक्ष न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में बयान देते हैं और उसी पर हस्ताक्षर करते हैं। इस तरह के हस्ताक्षरित बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई 'दस्तावेज' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उसमें "दस्तावेज" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -
>
> 'दस्तावेज' का अर्थ है अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से

> या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा किसी पदार्थ पर व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला, जिसका उपयोग करने का इरादा है, या जिसका उपयोग उस मामले को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
>
> परिभाषा को पढ़ने से पता चलता है कि किसी भी पदार्थ पर, लिखित रूप में व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला एक दस्तावेज है। 'दस्तावेज' की परिभाषा के तहत दिए गए पहले उदाहरण ने यह भी स्पष्ट किया कि 'एक लेखन एक दस्तावेज है'। इस प्रकार, तर्क के किसी भी खिंचाव से ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए और उनके द्वारा हस्ताक्षरित पक्षों के बयानों को नियम 3 के पहले भाग में उल्लिखित "लिखित रूप में और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित" की आवश्यकता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।
>
> (पैरा 17)

आगे कहा गया, कि शायद एकमात्र असाधारण परिस्थिति जिसके तहत एक पक्ष अदालत में या उसके वकील द्वारा दिए गए बयान से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है, जिसमें वह यह स्थापित करने में सक्षम हो सकता है कि ऐसा बयान धोखाधड़ी या धोखे के माध्यम से किया गया था। यहां तक कि ऐसे मामले में भी उसे आदर्श रूप से इस तरह के आदेश/निर्णय/डिक्री को कथित धोखाधड़ी के आधार पर विशेष रूप से दलील देकर और साथ ही इस तरह की धोखाधड़ी को स्थापित करने के लिए ठोस और ठोस सबूत देकर रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान मामले में कोई संदेह नहीं है कि वादी ने अपने आवेदन में, जिस पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, उसमें दलील दी है कि उसका बयान उसके वकील के प्रलोभन और मिलीभगत के कारण दर्ज किया गया था, लेकिन उक्त दावों को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। अगर याचिकाकर्ता वास्तव में अपने वकील की मिलीभगत के बारे में अपने रुख के बारे में आशावादी था, तो यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने अपने वकील के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई क्यों नहीं की। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी अपने वकील द्वारा कथित धोखाधड़ी और मिलीभगत के बारे में बार काउंसिल में कोई शिकायत दर्ज की थी। किसी भी पक्ष के लिए अपने वकील के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना बहुत सुविधाजनक है जब वह ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहता है जो उसके अनुकूल नहीं है। समझौते के संबंध में बयान याचिकाकर्ता/किरायेदार द्वारा न्यायालय में और उसके वकील की उपस्थिति में किया गया था और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 25.3.2019 को किरायेदार/याचिकाकर्ता लक्ष्मण द्वारा दिए गए बयान का अनुवादित सार निम्नलिखित प्रभाव से है:

"मैंने प्रतिवादी के साथ मामले में समझौता किया है। समझौते के अनुसार, मैं 20.4.2019 तक हस्तांतरित परिसर का खाली कब्जा मकान मालिक को सौंप दूंगा और मकान मालिक मुझे 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा। मैं अपने बयान से बाध्य रहूंगा।

(पैरा 18)

आगे यह भी कहा गया कि उपर्युक्त बयान एक न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायालय में दर्ज किए गए थे, जिसने ऐसे बयान दर्ज करने से पहले सभी सावधानी और सावधानी बरती होगी। बयान पक्षों के संबंधित वकीलों की उपस्थिति में दर्ज किए गए थे और जिन्होंने अदालत में उनकी विधिवत पहचान की थी। न्यायालय में न्यायिक अधिकारी के समक्ष दर्ज किए गए ऐसे बयानों को कम पवित्रता नहीं कहा जा सकता है, जो किसी शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा न्यायालय के बाहर तैयार किए गए समझौते के साधन से कम है। न्यायालय में एक पक्ष द्वारा दिए गए बयान के साथ एक निश्चित पवित्रता जुड़ी हुई है और यह माना जाना चाहिए कि इसे स्वेच्छा से दर्ज किया गया था। यदि किसी पक्ष को अपने वकील के खिलाफ या विरोधी वकील के खिलाफ कुछ तुच्छ आरोप लगाकर इस तरह के बयानों से बचने की अनुमति दी जाती है, तो यह वस्तुतः न्यायालय का मजाक उड़ाएगा।

(पैरा 20)

याचिकाकर्ता के वकील *विनय सैनी*।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता, जीएस साहनी।

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई कार्यवाही)

गुरविंदर सिंह गिल, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता ने हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम 1973, यमुना नगर के तहत जगाधरी में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 9.9.2019 के आदेश का विरोध किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें योग्यता के आधार पर उसकी अपील के निपटारे की मांग की गई थी।

2. इस याचिका के निपटान के लिए ध्यान देने योग्य कुछ तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी/मकान मालिकों ने हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 13 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता/किरायेदार को यमुनानगर में स्थित आवासीय परिसर से किराए और व्यक्तिगत आवश्यकता का भुगतान न करने के आधार पर बाहर निकालने की मांग की गई। किराया नियंत्रक, जगाधरी ने अनंतिम किराए का आकलन करते हुए दिनांक 8.8.2018 को एक आदेश पारित किया और

याचिकाकर्ता/किरायेदार को किराए की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता/किरायेदार ने अपीलीय प्राधिकारी (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) के समक्ष किराया नियंत्रक, जगाधरी के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 8.8.2018 के खिलाफ अपील की। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपरोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षों ने आपस में मामले का निपटारा किया और 25.3.2019 को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए, जिससे अपीलीय प्राधिकरण ने 25.3.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> उन्होंने कहा, 'दोनों पक्षों ने अलग-अलग दर्ज किए गए बयानों के आधार पर मामले को सुलझा लिया है. अब, मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 20.4.2019 तक स्थगित कर दिया गया है।
>
> एसडी/-
>
> Date : 25.3.2019 एड्ज/ जगाधरी"

3. उपरोक्त निपटान के बाद, मामले को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 20.4.2019 तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि, अगली तारीख को, याचिकाकर्ता/किरायेदार ने समझौते के लिए उसके द्वारा पहले दिए गए बयान का सम्मान करने के लिए कोई कदम उठाने के बजाय, योग्यता के आधार पर उसकी अपील के निपटारे की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह दलील दी गई कि उसे मकान मालिकों और उसके वकील द्वारा याचिकाकर्ता/किरायेदार के वकील के साथ मिलीभगत से समझौता करने के लिए एक बयान देने का लालच दिया गया था, जबकि वह ऐसा कोई बयान देने का इरादा नहीं रखता था। आवेदन के पैरा 2 से 4 (अनुलग्नक पी -3) में किए गए इस आशय के कथन निम्नानुसार हैं:

> "2. कि पहले 25.03.2019 को, अपीलकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा अदालत में कुछ बयान देने के लिए लुभाया गया था और अपीलकर्ता के पिछले वकील ने 25.3.2019 को अदालत में बयान पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए थे।
>
> 1. इसके बाद प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता को परेशान करना शुरू कर दिया और बिना किसी कारण या तुक के उसे धमकी दी और कहा कि उसने अपीलकर्ता को परिसर से बाहर निकालने के संबंध में अपना बयान दिया है।
>
> 3. तब अपीलकर्ता ने एक अन्य वकील को नियुक्त किया और कार्यवाही के बारे में पूछताछ की और पता चला कि प्रतिवादियों ने अपने वकील के साथ मिलीभगत से अपीलकर्ता का बयान दर्ज

किया है कि मामले में समझौता किया गया है और अपीलकर्ता प्रतिवादियों से 50,000/- रुपये प्राप्त करने के बाद 20.4.2019 तक परिसर खाली कर देगा, जबकि अपीलकर्ता ने ऐसा बयान देने का इरादा कभी नहीं किया था और उसका बयान प्रभाव और प्रलोभन."

4. हालांकि, उपरोक्त आवेदन को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9.9.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसे तत्काल पुनरीक्षण याचिका दायर करने के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि उत्तरदाताओं का दावा है कि मामले में समझौता किया गया था, लेकिन वास्तव में रिकॉर्ड पर लाए गए समझौते के बारे में कोई लिखित साधन नहीं था और यह एक ऐसा मामला है जहां किसी स्तर पर याचिकाकर्ता को 25.3.2019 को वकील के प्रलोभन और मिलीभगत के माध्यम से ऐसा बयान देने के लिए धोखा दिया गया था, लेकिन उक्त बयान उसी से पहले सुनवाई की अगली तारीख को वापस ले लिया गया था 20.4.2019 को कार्रवाई की जा सकती है और इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि पार्टियों के बीच कोई वैध समझौता था। विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 3 [इसके बाद 'सीपीसी' के रूप में संदर्भित] की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***गुरप्रीत सिंह*** *बनाम* ***चतुर भुज गोयल में की गई है***[1], ताकि यह माना जा सके कि लिखित समझौते की आवश्यकता अनिवार्य है।

6. याचिका का विरोध करते हुए, प्रतिवादी/जमींदारों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि किसी पक्ष द्वारा या कानून की अदालत में उसके वकील द्वारा दिए गए बयान को हल्के ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता है और अदालत में समझौते के लिए किसी पक्ष द्वारा दिए गए किसी भी बयान को कुछ शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष न्यायालय के बाहर किए गए समझौते की तुलना में कम पवित्रता नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ***गुरप्रीत सिंह के*** *मामले (सुप्रा) के*

[1] 1988 (1) एससीसी 270

बाद दिए गए निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न केवल समझौते के प्रति पार्टी द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार किया जा सकता है, बल्कि उनके मुवक्किल की ओर से वकील द्वारा दिए गए बयान को भी विधिवत सम्मानित और स्वीकार किया जाना चाहिए।

7. मैंने इस न्यायालय के समक्ष संबोधित प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। आगे बढ़ने से पहले सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के प्रावधानों को ध्यान में रखना उचित है, जैसा कि संशोधित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

आदेश 23 - सीपीसी का नियम 3

1. सूट का समझौता –

"जहां यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित होता है कि एक सूट को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी भी वैध समझौते या समझौते को समायोजित किया गया है, लिखित रूप में *और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित*, या जहां प्रतिवादी वादी को पूरे या किसी भी हिस्से के संबंध में संतुष्ट करता है वाद की विषय-वस्तु, न्यायालय इस तरह के समझौते का आदेश देगा, अभिलिखित किया जाने वाला समझौता या संतोष, और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगा, जहां तक यह वाद के पक्षकारों से संबंधित है, चाहे समझौते की विषय-वस्तु, समझौता या संतुष्टि वाद की विषय-वस्तु के समान हो या नहीं।

बशर्ते कि जहां एक पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार किया जाता है कि समायोजन या संतुष्टि पर पहुंच गया है, न्यायालय प्रश्न का फैसला करेगा; लेकिन प्रश्न का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, जब तक कि न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे स्थगन को देने के लिए उचित न समझे।

स्पष्टीकरण- कोई करार या समझौता जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1972 (1972 का 9) के अधीन शून्य या शून्यकरणीय है, इस नियम के अर्थान्तर्गत विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

8. यह ध्यान देने योग्य है कि 1976 से पहले लिखित रूप में समझौते को हटाने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं थी और यह वर्ष 1976 में संशोधन के माध्यम से था कि उक्त

आवश्यकता को सीपीसी के आदेश 23 के नियम 3 में "*लिखित रूप में और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित*" शब्दों को सम्मिलित करके शामिल किया गया था। 1976 के संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन के प्रासंगिक भाग में कहा गया है कि:

"यह प्रदान किया गया है कि नियम 3 के तहत एक समझौता या समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह मुकदमे की प्रगति में देरी के लिए मौखिक समझौतों या समझौतों की स्थापना से बचने के उद्देश्य से है।

9. इस न्यायालय के समक्ष रखा गया प्रश्न यह है कि क्या किसी ऐसे मामले में जिसमें समझौता किया गया है, सभी परिस्थितियों में, यह अनिवार्य है कि इस तरह के समझौते को एक उपकरण के माध्यम से लिखित रूप में लिया जाना चाहिए और क्या लिखित साधन के अभाव में समझौता लागू नहीं किया जा सकता है या उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

10. सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के संशोधित प्रावधानों को पढ़ना, जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, यह सुझाव देता है कि एक समझौता लिखित रूप में होना चाहिए। ***गुरप्रीत सिंह के*** *मामले (सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जहां एक वकील द्वारा समझौते के प्रति बयान दिया गया था, इस प्रकार था:

"10. नियम 3 के तहत, जैसा कि अब यह खड़ा है, जब वाद में एक दावे को किसी भी वैध समझौते या समझौते द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, तो समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, उनके बीच एक पूर्ण समझौता होना चाहिए। एक समायोजन का गठन करने के लिए, समझौता या समझौता स्वयं एक डिक्री में सन्निहित होने में सक्षम होना चाहिए। जब पक्ष अपील के एक सूट की सुनवाई के दौरान एक समझौता करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक उपकरण के रूप में लिखित रूप में समझौता कम किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय को पार्टियों पर जोर देना चाहिए कि वे शर्तों को लिखित रूप में कम करें।

11.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जिनेश्वरदास (डी) के माध्यम से L.Rs ***और अन्य बनाम*** *श्रीमती जगरानी और एक अन्य* ***मामले में बाद के मामले में***[2] अवलोकन किया

12.स्पष्ट शब्दों में कि यदि किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील समझौते की दिशा में बयान देता है, तो पार्टी इसके लिए समान रूप से बाध्य होगी। उक्त मामले में, पक्षकार विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद के संबंध में मुकदमा कर रहे थे, जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष अपील (आरएसए) के लंबित रहने के दौरान, संबंधित वकील ने बयान दिया कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा 9.5.2002 को ***जिनेश्वरदास*** *के मामले (सुप्रा)* में दर्ज आदेश इस प्रकार है:

पीठ ने कहा, "दोनों वकील इस मामले को सुलझाने के लिए सहमत हैं। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी एक महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को 25,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा, अन्यथा यह आज की तारीख से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देगा। इस सहमत सबमिशन पर, इस अपील का फैसला किया जाता है और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

1. प्रतिवादी एक महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को 25,000 /

2. यदि यह राशि 10 जून, 2002 को या उससे पहले अदालत में जमा नहीं की जाती है, तो उपरोक्त राशि की वसूली तक @ 12% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा।

3. मुकदमेबाजी की लागत दोनों पक्षों द्वारा वहन की जाएगी।

उपरोक्त सहमत प्रस्तुतियों के मद्देनजर अपील का निपटारा किया जाता है।

13.हालांकि, बाद में, जिनेश्वरदास के ***मामले (सुप्रा)*** *में अपीलकर्ताओं ने* इस आधार पर आदेश 9.5.2002 की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया कि चूंकि अपील मुख्य रूप से समझौते के आधार पर निपटाई गई थी, इसलिए आदेश 23 नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के

---

[2] 2003 (11) एससीसी 372

प्रावधानों के संदर्भ में लिखित रूप में समझौता किया जाना आवश्यक था। और वही लिखित रूप में नहीं किया गया है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है, इस तरह के समझौते को अपील के निपटान का आधार नहीं बनाया जा सकता है. उसमें यह भी तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय में अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील द्वारा इस संबंध में की गई प्रस्तुति, यदि कोई हो, अपीलकर्ताओं के किसी भी निर्देश के बिना थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि अपील का निपटान करने वाले दिनांक 9.5.2002 के आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए। तथापि, दिनांक 15-7-2002 के आदेश द्वारा पुनरीक्षा आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई जिसमें ***गुरप्रीत सिंह के*** मामले (सुप्रा) पर यह तर्क देने के लिए अत्यधिक भरोसा किया गया कि लिखित समझौते के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 में निहित उपबंधों के अनुपालन के अभाव में उच्च न्यायालय का निर्णय कायम नहीं रह सका।

14. हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले यानी ***बायराम पेस्टनजी गरीवाल*** *बनाम* ***यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर***[3] भरोसा करते हुए अपील को खारिज कर दिया। ***जिनेश्वरदास*** *के मामले (सुप्रा)* में दिए गए फैसले से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"7. हमने दोनों पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हालांकि, *गुरप्रीत सिंह* के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने नियम 3 आदेश 23 सिविल प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य और उद्देश्य को समझाया, "लिखित रूप में और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित" शब्दों पर जोर देकर, झूठी और तुच्छ दलीलों को रोकने के लिए आवश्यक है कि एक सूट को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी भी वैध समझौते या समझौते द्वारा समायोजित किया गया था ताकि मुकदमे में कार्यवाही को लंबा या देरी की जा सके। उसमें यह भी देखा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 3 आदेश 23 के अनुसार, जब वाद में किसी दावे को किसी विधिपूर्ण करार या समझौते द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, तो ऐसा समझौता

[3] 1992 (1) एससीसी 31

लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उनके बीच पूर्ण समझौता होना चाहिए और समायोजन का गठन करने के लिए समझौता या समझौता स्वयं एक डिक्री में सन्निहित होने में सक्षम होना चाहिए। तथ्य यह है कि पार्टियों ने सूट या अपील की सुनवाई के दौरान एक समझौता किया था, उक्त नियम की आवश्यकता को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था और अदालतों से अपेक्षा की गई थी कि वे पार्टियों को लिखित रूप में शर्तों को कम करने के लिए जोर दें। *बायराम पेस्टनजी गारीवाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य [(1992) 1 एससीसी 31)* में, इस न्यायालय ने 1976 में नियम 3 आदेश 23 सिविल प्रक्रिया संहिता में बहुत संशोधन का विज्ञापन करते हुए, नियम 1 आदेश 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ और की ओर से कार्य करने के लिए लगे वकील के अधिकार के विषय पर केस लॉ की व्यापक समीक्षा पर भी आवश्यक प्रभाव देखा। ग्राहक ने निम्नानुसार देखा:

' 37. हम, तथापि, यह सलाहकार निहित प्राधिकारी पर कार्रवाई नहीं के लिए विवेकपूर्ण होगा कि जोड़ने के लिए विवेकपूर्ण हो सकता है, सिवाय जब परिस्थितियों की अत्यावश्यकता समझौते या समझौते द्वारा सूट के तत्काल समायोजन की मांग से वारंट और पार्टी के हस्ताक्षर अनुचित देरी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है. आसान और त्वरित संचार के इन दिनों में, ऐसी आकस्मिकता शायद ही कभी उत्पन्न हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि एक बुद्धिमान और सावधान वकील खुद को पहले से ही लिखित रूप में व्यक्त आवश्यक अधिकार के साथ ऐसी सभी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करेगा ताकि न तो उसके अधिकार पर और न ही अखंडता पर कभी संदेह हो। यह आवश्यक एहतियात वकील की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा और साथ ही कानूनी पेशे की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखेगा।

15. सामान्य कानून प्रणाली में वकील की पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका को ध्यान में रखते हुए, और सीपीसी (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संसद द्वारा दूर की जाने वाली बुराई को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में समझौते की शर्तों को कम करके मामलों की निश्चितता और शीघ्र निपटान की प्राप्ति, और समझौते डिक्री को वाद के विषय वस्तु के बाहर आने वाले मामलों को भी समझने की अनुमति देना, लेकिन

पार्टियों से संबंधित, विधायिका इस तरह के प्रभाव के व्यक्त शब्दों के अभाव में पार्टियों को उनके कारण में वकील द्वारा या उनके विधिवत अधिकृत एजेंटों द्वारा समझौता करने से रोकने के लिए नहीं माना जा सकता है। ऐसी कोई भी धारणा अनिश्चितताओं को समाप्त करके और समझौते के दायरे को बढ़ाकर अदालत में बकाया मामलों में त्वरित कमी लाने के विधायी उद्देश्य के साथ असंगत होगी।

16. पार्टी पर व्यक्तिगत रूप से समझौते या समझौते पर हस्ताक्षर करने पर जोर देने के लिए अक्सर अनुचित देरी, हानि और असुविधा होती है, खासकर अनिवासी व्यक्तियों के मामले में। यह हमेशा सार्वभौमिक रूप से समझा गया है कि एक पार्टी हमेशा अपने कर्तव्य अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य कर सकती है। यदि एक पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक अपने प्रिंसिपल की ओर से एक समझौते या समझौता में प्रवेश कर सकता है, तो वकालतनामा द्वारा अपेक्षित प्राधिकरण रखने वाले वकील अपने मुवक्किल की ओर से कार्य कर सकते हैं। ऐसी क्षमता को मान्यता नहीं देना न केवल व्यक्तिगत रूप से पार्टियों को बहुत असुविधा और नुकसान पहुंचाना है, बल्कि अदालत में कार्यवाही की प्रगति में देरी करना भी है। यदि विधायिका ने देरी, असुविधा और अनावश्यक व्यय के जोखिम पर भी इस तरह के मौलिक परिवर्तन करने का इरादा किया होता, तो यह स्पष्ट रूप से ऐसा कहा जाता।

17. तदनुसार, हमारा विचार है कि सी.पी.सी. (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा सम्मिलित शब्द 'लिखित रूप में और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित' का अर्थ आवश्यक रूप से आदेश 3 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता की भाषा उधार लेना होना चाहिए।

"किसी भी अदालत में या किसी भी अदालत में कोई उपस्थिति, आवेदन या कार्य, कानून द्वारा आवश्यक या अधिकृत ऐसे न्यायालय में किसी पार्टी द्वारा किए जाने या किए जाने के लिए, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा किसी भी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, पार्टी द्वारा व्यक्तिगत रूप से, या उसके मान्यता प्राप्त एजेंट द्वारा, या एक वकील द्वारा किया जा सकता है या किया जा सकता है, उसकी ओर से उपस्थित होना, आवेदन करना या कार्य करना।

परन्तु ऐसी कोई उपस्थिति, यदि न्यायालय ऐसा निदेश दे, तो पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

18. हम कानून के उपरोक्त कथन के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। नतीजतन, अपीलकर्ता के लिए इसके विपरीत संघर्ष करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा हमारा यह भी विचार है कि अदालत के समक्ष आम सहमति के परिणामस्वरूप पारित निर्णय या डिक्री को हमेशा समझौता या निपटान और समायोजन पर पारित नहीं कहा जा सकता है। यह कई बार प्रवेश पर एक निर्णय भी हो सकता है, जैसा कि इस मामले में है।

19. दूसरे शब्दों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की स्थिति को दोहराया कि एक वकील अपने मुवक्किल की ओर से विवाद से समझौता कर सकता है और इसके बाद की डिक्री न्यायालय के समक्ष बनी आम सहमति का परिणाम हो सकती है और यह कि आम सहमति जरूरी नहीं कि एक समझौता या समझौता और समायोजन हो और वही, किसी दिए गए मामले में, प्रवेश पर निर्णय हो सकता है।

20. एक अन्य मामले में अर्थात ***पुष्पा देवी भगत (डी) एलआर श्रीमती साधना राय*** *बनाम* ***राजिंदर सिंह और अन्य***[4] के माध्यम से, जहां एक किरायेदार बेदखली आवेदन के दौरान एक निश्चित तारीख तक परिसर खाली करने के लिए सहमत हो गया और ट्रायल कोर्ट ने दोनों वकीलों के बयान दर्ज किए और उसके बाद एक सहमति डिक्री पारित की जिसे बाद में किरायेदार द्वारा चुनौती दी गई, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय द्वारा अभिलिखित रूप में दिए गए बयानों से समझौता होगा। प्रासंगिक उद्धरण इस तरह पढ़ता है:

"24. अब हम नियम 3 में 'लिखित रूप में' की आवश्यकता की ओर मुड़ते हैं। इस मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, वादी के वकील और प्रतिवादी के वकील के संबंधित बयानों को समझौते की शर्तों के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा शपथ पर दर्ज किया गया था और उन बयानों को पढ़ने और सही होने के बाद स्वीकार किए जाने के बाद, उक्त वकील द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यदि एक आवेदन या याचिका के रूप में एक कागज पर लिखे गए

[4] 2006 (5) एससीसी 566

समझौते की शर्तों को लिखित रूप में एक समझौता माना जाता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि अदालत द्वारा लिखित रूप में दर्ज शपथ पर विशिष्ट और स्पष्ट बयान और बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत पढ़ा और सही माना जाता है और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, क्या लिखित में नहीं कहा जा सकता है? जाहिर है, नहीं। हम इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का भी उल्लेख कर सकते हैं जो किसी दस्तावेज को अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए या जिनका उपयोग किया जा सकता है, द्वारा किसी पदार्थ पर व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित करता है। इसलिए, अदालत द्वारा दर्ज किए गए बयान लिखित रूप में एक समझौता होगा।

21. नतीजतन, पार्टियों या उनके वकील के बयान, अदालत द्वारा दर्ज किए गए और बयान देने वाले व्यक्तियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, 'पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में बयान' होगा। हालांकि, अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि समझौते की शर्तें वैध हैं। इस मामले में हम ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से पाते हैं कि दूसरे प्रतिवादी ने अपने वकील श्री दिनेश गर्ग को मुकदमे के संबंध में उसके लिए कार्य करने और किसी भी समझौते में प्रवेश करने का अधिकार देते हुए वकालतनामा निष्पादित किया था। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि श्री दिनेश गर्ग को दूसरे प्रतिवादी द्वारा समझौता करने के लिए अधिकृत किया गया था। हम यह भी पाते हैं कि वादी के वकील और प्रतिवादियों के वकील ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष शपथ पर गंभीर बयान दिए, जिसमें समझौते की शर्तों को निर्दिष्ट किया गया था, जो लिखित रूप में विधिवत दर्ज किए गए थे और उनके द्वारा हस्ताक्षरित थे। नियम 3 आदेश 23 के पहले भाग की आवश्यकताएं इस मामले में पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

22. उपरोक्त कानूनी स्थिति को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, ***बख्शी देव राज और अन्य*** *बनाम* ***सुधीर कुमार***[5] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपील वापस लेने या डिक्री के संशोधन के लिए ग्राहक से निर्देशों पर बयान देने वाला वकील उसकी क्षमता के भीतर है, हालांकि यह जोड़ना जल्दबाजी में कहा गया है

[5] 2011 (8) एससीसी 679

कि मुवक्किल से लिखित रूप में ऐसे निर्देश प्राप्त करना वांछनीय है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों से स्पष्ट कानून की स्थिति, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी पक्ष या उसके वकील द्वारा समझौते के प्रति दिया गया बयान जो लिखित रूप में लिया गया है, एक लिखित समझौते के रूप में अच्छा है और आदेश 23 नियम 3 सीपीसी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, विशेष रूप से नियम 3 में प्रावधान के संबंध में जो वर्ष 1976 में संशोधन के माध्यम से डाला गया था अर्थात "*लिखित रूप में और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित*"। हमारे उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के निर्णय का भी उल्लेख करना असंगत नहीं होगा जिसमें दस्तावेज शब्द की परिभाषा के संदर्भ में इसी मुद्दे पर चर्चा की गई है। ***श्रीमती रक्षा रानी*** *बनाम* ***राम लाल (डीबी)***[6] से प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार है:

> "5 .... बेशक, ट्रायल कोर्ट द्वारा पार्टियों के बयान दर्ज किए गए थे जिनमें समझौते की शर्तें थीं जिन पर उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। क्या यह कहा जा सकता है कि समझौते को लिखित रूप में नहीं माना जाना चाहिए और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाना चाहिए? क्या कागज के एक टुकड़े पर लिखे गए और उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों को न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में दिए गए उनके स्पष्ट बयानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिस पर उन्होंने विधिवत हस्ताक्षर किए थे? हमारी स्पष्ट राय में, नियम 3 के पहले भाग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संतुष्ट किया जाता है जब पक्ष न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में बयान देते हैं और उसी पर हस्ताक्षर करते हैं। इस तरह के हस्ताक्षरित बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई 'दस्तावेज' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उसमें "दस्तावेज" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -
>
> > 'दस्तावेज' का अर्थ है अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा किसी पदार्थ पर व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला, जिसका उपयोग करने का इरादा है, या जिसका उपयोग उस मामले को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
>
> परिभाषा को पढ़ने से पता चलता है कि किसी भी पदार्थ पर, लिखित रूप में व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला एक दस्तावेज है।

---

[6] 1987 एआईआर (पंजाब एवं घंटा) 60

'दस्तावेज' की परिभाषा के तहत दिए गए पहले उदाहरण ने यह भी स्पष्ट किया कि 'एक लेखन एक दस्तावेज है'। इस प्रकार, तर्क के किसी भी खिंचाव से ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए और उनके द्वारा हस्ताक्षरित पक्षों के बयानों को नियम 3 के पहले भाग में उल्लिखित "लिखित रूप में और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित" की आवश्यकता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

24. शायद एकमात्र असाधारण परिस्थिति जिसके तहत एक पक्ष अदालत में या उसके वकील द्वारा दिए गए बयान से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है, जिसमें वह यह स्थापित करने में सक्षम हो सकता है कि ऐसा बयान धोखाधड़ी या धोखे के माध्यम से किया गया था। यहां तक कि ऐसे मामले में भी उसे आदर्श रूप से इस तरह के आदेश/निर्णय/डिक्री को कथित धोखाधड़ी के आधार पर विशेष रूप से दलील देकर और साथ ही इस तरह की धोखाधड़ी को स्थापित करने के लिए ठोस और ठोस सबूत देकर रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान मामले में कोई संदेह नहीं है कि वादी ने अपने आवेदन में, जिस पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, उसमें दलील दी है कि उसका बयान उसके वकील के प्रलोभन और मिलीभगत के कारण दर्ज किया गया था, लेकिन उक्त दावों को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। अगर याचिकाकर्ता वास्तव में अपने वकील की मिलीभगत के बारे में अपने रुख के बारे में आशावादी था, तो यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने अपने वकील के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई क्यों नहीं की। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी अपने वकील द्वारा कथित धोखाधड़ी और मिलीभगत के बारे में बार काउंसिल में कोई शिकायत दर्ज की थी। किसी भी पक्ष के लिए अपने वकील के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना बहुत सुविधाजनक है जब वह ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहता है जो

उसके अनुकूल नहीं है। समझौते के संबंध में बयान याचिकाकर्ता/किरायेदार द्वारा न्यायालय में और उसके वकील की उपस्थिति में किया गया था और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 25.3.2019 को किरायेदार/याचिकाकर्ता लक्ष्मण द्वारा दिए गए बयान का अनुवादित सार निम्नलिखित प्रभाव से है:

"मैंने प्रतिवादी के साथ मामले में समझौता किया है। समझौते के अनुसार, मैं 20.4.2019 तक हस्तांतरित परिसर का खाली कब्जा मकान मालिक को सौंप दूंगा और मकान मालिक मुझे 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा। मैं अपने बयान से बाध्य रहूंगा।

25. उत्तरदाताओं / जमींदारों को भी निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक बयान का सामना करना पड़ा:

"मैंने किरायेदार द्वारा दिए गए बयान को सुना और समझा है और इसे सही माना है। मैं अपने बयान से बाध्य रहूंगा।

26. उपर्युक्त बयान एक न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायालय में दर्ज किए गए थे, जिन्होंने ऐसे बयान दर्ज करने से पहले सभी सावधानी और सावधानी बरती होगी। बयान पक्षों के संबंधित वकीलों की उपस्थिति में दर्ज किए गए थे और जिन्होंने अदालत में उनकी विधिवत पहचान की थी। न्यायालय में न्यायिक अधिकारी के समक्ष दर्ज किए गए ऐसे बयानों को कम पवित्रता नहीं कहा जा सकता है, जो किसी शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा न्यायालय के बाहर तैयार किए गए समझौते के साधन से कम है। न्यायालय में एक पक्ष द्वारा दिए गए बयान के साथ एक निश्चित पवित्रता जुड़ी हुई है और यह माना जाना चाहिए कि इसे स्वेच्छा से दर्ज किया गया था। यदि किसी पक्ष को अपने वकील के खिलाफ या विरोधी वकील के खिलाफ कुछ तुच्छ आरोप लगाकर इस तरह के बयानों से बचने की अनुमति दी जाती है, तो यह वस्तुतः न्यायालय का मजाक उड़ाएगा।

27. यह स्पष्ट है कि यह शामिल करने का बहुत उद्देश्य कि एक समझौता लिखित रूप में होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ श्वेत-श्याम रूप में है और समझौते की शर्तों के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है ताकि दोनों में से कोई भी पक्ष बाद के चरण में कुछ शर्तों पर पीछे हटने के लिए न मुड़ें या निपटान के कुछ नियमों और शर्तों की गलत व्याख्या करने का प्रयास करें, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है। इसका उद्देश्य न्यायालय के अनुचित उत्पीड़न और कीमती समय की बर्बादी से बचना था ताकि पक्षकार बार-बार मामले को उत्तेजित करते रहें। ***पुष्पा देवी भगत के*** *मामले (सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में किरायेदारों द्वारा समझौते के संबंध में तुच्छ और कष्टप्रद विवाद उठाकर मुकदमेबाजी को अनिश्चित काल तक लंबा खींचने और अदालत को दिए गए गंभीर वचन पर वापस जाने के प्रयासों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

28. जिनेश्वरदास के मामले (सुप्रा), *बायराम पेस्टनजी गैरीवाल* के मामले (सुप्रा), ***पुष्पा देवी भगत के मामले (सुप्रा) और*** *बख्शी देव राज* के मामले ***(सुप्रा)*** *में निर्धारित कानूनी स्थिति के आलोक में उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की जांच* करना ***, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और यह पता लगाने पर कि*** यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता के वकील और इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। याचिका बिना योग्यता के है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अपीलीय प्राधिकारी या निष्पादन न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.9.2019 में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए, महामारी के प्रसार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, पार्टियों को उचित समय देगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य

के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा